E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 01-10-2024
Accepted: 03-12-2024
Published: 21-01-2025

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 3; Issue 1; 2025; Page No. 243-246

सार्वजनिक रोजगार से संबंधित समस्याएं और समाधान

[1]मनीष कुमार सोनी, [2]रवि प्रकाश पाण्डेय

[1]अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, मध्य प्रदेश, भारत
[2]शारदा महाविद्यालय मैहर जिला-मैहर, मध्य प्रदेश, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17811267

Corresponding Author: मनीष कुमार सोनी

सारांश

कई स्व-रोज़गार करने वाले लोग, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले, संगठित संस्थाओं से ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। स्व-रोज़गार उन लोगों के लिए एक लाभदायक और लचीला करियर विकल्प हो सकता है जो इससे जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ और जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। यह स्वतंत्रता, संभावित वित्तीय लाभ और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, वित्तीय प्रबंधन और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि इन विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को अधिक जागरूकता और कौशल-आधारित शिक्षा के माध्यम से उद्यमशीलता के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए विशेष उपचार दिया जाए।

मूल शब्दः सार्वजनिक रोजगार, समस्याएं, समाधान, भारत सरकार, बेरोजगार

प्रस्तावना

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना (SEEUY) भारत सरकार द्वारा 1983 में शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य पैकेज्ड सहायता के प्रावधान के माध्यम से उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करना था। 1991 में नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत करने के बाद, भारत सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) योजना तैयार की गई जिसे 2 अक्टूबर -1993 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य लाभार्थियों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उठाए गए कदम तभी सफल होंगे जब विकास का लाभ समुदाय के सबसे निचले तबके तक पहुंचे। सरकार ने इस तथ्य को मान्यता दी है कि जमीनी स्तर की योजना या सूक्ष्म स्तर की योजना पर अधिक जोर दिया जाता है जहां फोकस ग्रामीण विकास पर होता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में तेजी लाने के लिए 7 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके 10 लाख लोगों को अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था और प्रारंभिक सफलता को देखते हुए, अब इसे भारत सरकार की एक स्थायी योजना के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें इसके सफल कार्यान्वयन और जिस उद्देश्य के लिए इसे डिजाइन किया गया है उसे पूरा करने के लिए रूपरेखा और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्वरोजगार सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के एक समग्र ऋण प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण राशि एक लाख रुपये और सेवा और औद्योगिक गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपये है। देश में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों को इस योजना को वित्तपोषित करना आवश्यक है। 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी शिक्षित बेरोजगार युवा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है। लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 40,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में महिलाओं और वंचित समुदायों की सुरक्षा को उचित महत्व दिया गया है। इस योजना के तहत शुरू की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियाँ इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। समूह गतिविधियाँ भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, लेकिन समूह गतिविधियों के लिए ऋण राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उद्यम की प्रकृति और लाभप्रदता के आधार पर ऋण राशि को 7 वर्षों के भीतर चुकाना होगा। लाभार्थी सरकार से परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की सब्सिडी के लिए पात्र हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपये है। चयनित आवेदकों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उनकी योजना का कार्यान्वयन और समन्वय केंद्रीय स्तर पर उच्च शक्ति समिति द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य PMRY समिति और जिला स्तर पर जिला PMRY समिति द्वारा किया जाता है।

भारत इतने लंबे समय से उन्नति की यात्रा पर है, लेकिन समग्र प्रक्रिया में स्वच्छता और सफाई के प्रमुख क्षेत्र की अनदेखी की गई है। खुले में कूड़ा फेंकने, खुले में शौच की समस्या से निपटने और स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस मिशन के तहत, भारत ने अक्टूबर 2019 में खुले में शौच मुक्त होने की घोषणा की। चूंकि यह कार्यक्रम के चरण । का हिस्सा रहा है, अब मिशन चरण ॥ में प्रवेश कर रहा है जिसने इस मिशन के वास्तविक उद्देश्य को आगे बढ़ाया है।

स्वरोजगार को "किसी भी क्षेत्र में अपनी आय और रोजगार सृजन गतिविधि में काम करना" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे आगे भी विस्तारित किया जा सकता है क्योंकि वे सभी लोग जिनके पास आय के अपने साधन हैं और जो आय उत्पन्न करने के लिए अपने श्रम का उपयोग करते हैं, वे स्वरोजगार हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए कई कार्यक्रम विकसित किए हैं; अब तक अपनाई गई स्वरोजगार की रणनीति परिवारों को न्यूनतम आय अर्जित करने में मदद करने पर केंद्रित रही है जो उन्हें गरीबी रेखा पार करने में सक्षम बनाती है।

पिछले अध्ययनों का विश्लेषण

मुस्तफा (2024) [24] यह शोधपत्र भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन और समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू की गई विभिन्न योजनाओं की जांच करता है। गरीबी उन्मूलन भारत के विकास एजेंडे में एक केंद्रीय विषय रहा है, जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने और आजीविका बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और नीतियां बनाई गई हैं। यह अध्ययन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और अन्य प्रमुख पहलों जैसी प्रमुख योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है। गरीबी को कम करने में इन योजनाओं की प्रभावशीलता और उनकी चुनौतियों पर चर्चा की गई है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए संभावित सुधारों और भविष्य की दिशाओं के बारे में जानकारी मिलती है।

सिंह, रागिनी. (2024) [7]. इस शोधपत्र का उद्देश्य सरकार द्वारा एमएसएमई के बजटीय आवंटन और उपयोग के रुझानों का पता लगाना और एमएसएमई के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को जानना है। एमएसएमई के लिए सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के रुझानों को जानने के लिए तालिकाओं और ग्राफ़िकल विधियों का उपयोग किया गया है। एमएसएमई की इन वार्षिक रिपोर्टों का उपयोग किया गया है, इसलिए यह द्वितीयक डेटा पर आधारित है। अध्ययन में पाया गया है कि सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए पर्याप्त निधि भी आवंटित की है जो अगले वर्ष में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है और उपयोग की प्रवृत्ति भी बढ़ रही थी। सरकार ने बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं में प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कारीगरों और एमएसएमई श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की क्षमता बढ़ाने से एमएसएमई के लिए सरकारी बजटीय आवंटन और उपयोग में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। नवाचार, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और नौकरियों का विकास सभी इस मदद से हो सकते हैं। चूंकि एमएसएमई अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त वित्त से सबसे अधिक लाभ होता है, जो उत्पादन को बढ़ाता है और नए बाजार खोलता है। इससे एक अधिक गतिशील और विविधतापूर्ण व्यावसायिक माहौल बनता है, जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है। एमएसएमई कार्यक्रमों को समझना यह गारंटी देता है कि छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय प्रभावी रूप से सुलभ संसाधनों, वित्तीय सहायता और समर्थन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस बेहतर पहुंच की बदौलत एमएसएमई अब बाजार में विस्तार, विकास और प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक सुसज्जित हैं।

डॉ-अब्दल और कुरैशी (2024) [6] यह अध्ययन महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से भारतीय सरकार की योजनाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हाल के वर्षों में, भारत में महिलाओं ने उद्यमिता में महत्वपूर्ण प्रगति की है, पारंपरिक भूमिकाओं से संक्रमण कर अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदानकर्ता बन गई हैं। इस प्रगति के बावजूद, महिला उद्यमियों को वित्तीय बाधाओं, सामाजिक पूर्वाग्रहों, संसाधनों तक पहुंच की कमी और कौशल विकास के अपर्याप्त अवसरों सहित बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह शोध इन चुनौतियों को कम करने और महिलाओं को उनके उद्यमशीलता के प्रयासों में सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई विभिन्न सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का पता लगाता है। मात्रात्मक सर्वेक्षण और गुणात्मक साक्षात्कार सहित मिश्रित-विधियों के दृष्टिकोण के माध्यम से, अध्ययन महिलाओं की उद्यमशीलता की सफलता पर इन योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि जहां सरकारी पहलों ने वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करने में सकारात्मक प्रगति की है अध्ययन का निष्कर्ष सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सिफारिशों के साथ समाप्त होता है, जिसमें लक्षित पहुंच, अनुरूप सहायता कार्यक्रम और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करना शामिल है। सरकारी सहायता और महिलाओं की उद्यमशीलता चुनौतियों के बीच संबंधों को उजागर करके, इस शोध का उद्देश्य भारत में अधिक समावेशी और न्यायसंगत उद्यमशीलता परिदृश्य में योगदान देना है।

गुप्ता (2023) [5] माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, "नई पीढ़ी का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और यह आत्मनिर्भर भारत की नींव है।" एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जाना जाता है; जो लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन में 30% से अधिक का योगदान देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसएमई को इन एमएसएमई योजनाओं का सभी लाभ उचित समय पर मिले, भारत सरकार ने पहल की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के आर्थिक विकास और विस्तार के लिए आवश्यक हैं। यह क्षेत्र निर्यात, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास में विशिष्ट योगदान देता है। पूरे देश में एमएसएमई के विस्तार और स्थिरता को

प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने कई नीतियाँ और पहल की हैं। फिर भी, एमएसएमई के सामने आधिकारिक ऋण, रोजगार सृजन, सरकार को सीधे बिक्री, उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण, माइक्रोक्रेडिट प्राप्त करने, अज्ञानता और अन्य मुद्दों से संबंधित कई बाधाएँ हैं। नई फर्मों को जमीन पर उतरने में मदद करने के लिए, सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहले से ही कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। लेकिन, विभिन्न उपयुक्त योजनाओं के बारे में जानकारी की कमी के कारण, कई इकाइयों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैंकों और अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों से वित्तपोषण प्राप्त करने का प्रयास करते समय एमएसएमई के सामने अभी भी कई चुनौतियाँ और बाधाएँ हैं। हालाँकि सरकार ने इस उद्योग को ऋण प्रवाह की सुविधा के लिए पहले से ही बड़े कदम उठाए हैं, फिर भी एमएसएमई क्षेत्र की वास्तविक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि यह अधिक रोजगार संभावनाएँ पैदा करता है और मुद्रास्फीति, बड़े पैमाने पर बजट घाटे, गरीबी और भुगतान असंतुलन सहित अन्य व्यापक आर्थिक मुद्दों को कम करने के सरकार के प्रयासों में सहायता करता है। वर्तमान अध्ययन एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार की पहल और वर्तमान परिदृश्य में महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति को दर्शाता है।

नाइक (2022) [4] उद्यमिता आर्थिक प्रणाली में गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण तत्व पेश करती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रणाली में गतिशीलता की शुरूआत जैसे परिवर्तनों की एक श्रृंखला पेश की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत में आर्थिक विकास और वृद्धि का एक ठोस आधार प्रदान कर रहे हैं। MSME को भारत सहित लगभग सभी देशों के सभी औद्योगिक प्रयासों की नींव के रूप में लिया जाता है। वे दुनिया भर में बड़े व्यवसायों के योगदान में सहायता कर रहे हैं। जहां तक भारत का संबंध है, इन MSME के कारण देश का आर्थिक विकास और प्रगति काफी हद तक फल-फूल रही है। भारत में, देश में उद्यमिता विकास के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न पहल की गई हैं। उद्यमिता ने भारत में नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया सहित कई उच्च-स्तरीय पहल शुरू की गई हैं। हालांकि, विकास में उद्यमिता की भूमिका कई नीति पर्यवेक्षकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य भारत में उद्यमिता और "स्टार्टअप इंडिया" योजना के तहत इसके प्रचार के बारे में अध्ययन करना है। यह अध्याय पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेबसाइटों और समाचार पत्रों के अलावा साक्ष्य के कई स्रोतों से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा पर आधारित है।

अनुसंधान क्रियाविधि

शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी उपलब्ध सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रकाशनों, पत्रिकाओं, जर्नलों एवं दैनिक समाचार पत्रों का अध्ययन करके प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सांख्यिकीय विधियों द्वारा आँकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों की वास्तविकता से तुलना करके विसंगतियों का पता लगाया जाता है। शोध कार्य हेतु क्षेत्र अध्ययन एवं विचार-नमूनाकरण विधियों का समुचित प्रयोग किया जाता है, जिससे शोध कार्य को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है तथा अपेक्षित निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

प्रस्तुत शोध का क्षेत्र सीधी जिला है, जिसके अंतर्गत केवल चार विकासखंड सीधी, कुसमी, रामपुर नैकिन और सिहावल शामिल हैं। इन चार विकासखंडों से प्रत्येक 75 परिवारों से 300 सूचनादाताओं का चयन लॉटरी नमूनाकरण विधि द्वारा किया गया है। कंप्यूटर में एसपीएसएस और एक्सेल पैकेज के माध्यम से डेटा को संसाधित किया गया।

डेटा विश्लेषण

तालिका 1 में इकाई शुरू करने और चलाने में लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 70 प्रतिशत नमूना लाभार्थियों को इकाई शुरू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। 300 नमूना लाभार्थियों में से जिन्हें इकाई शुरू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, बिजली कनेक्शन मिलने में देरी भी एक समस्या थी जिसका लाभार्थियों ने सामना किया, इससे उनके उत्पादन और विपणन पर असर पड़ा। 12 प्रतिशत को बिजली कनेक्शन मिलने में देरी का सामना करना पड़ा और 13 प्रतिशत को समय पर मशीनरी मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा। 17 प्रतिशत लाभार्थी सामग्री की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हुए और 28 प्रतिशत कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हुए। इकाई शुरू करने के समय औद्योगिक इकाई में कुशल श्रमिकों को प्राप्त करना एक बड़ी कठिनाई है।

तालिका 1: योजनाओं में नमूना लाभार्थियों द्वारा इकाई शुरू करने में आने वाली समस्या

सामान			
यूनिट शुरू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा		लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
	हाँ	210	70
	नहीं	90	30
		300	100
इकाई शुरू करने में अनुभव की गई कठिनाई की प्रकृति	बिजली मिलने में देरी कनेक्शन	36	12
	प्राप्त करने में देरी मशीनरी	39	13
	की अनुपलब्धता सामग्री	51	17
	की अनुपलब्धता कुशल श्रमिक	84	28
		210	70

इकाई चलाने में समस्याएँ

इकाई चलाने में लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को तालिका 6.2 में दिखाया गया है, तालिका से पता चलता है कि इकाई चलाने के समय 99 प्रतिशत लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी का सामना करने वाले 300 लाभार्थियों में से, यह दर्शाता है कि बुनियादी ढांचागत सुविधाएं चिंता का विषय हैं, 54 प्रतिशत ने खुलासा किया कि बिजली की विफलता ने उनकी इकाइयों को प्रभावित किया है। बिजली की आपूर्ति की कमी ने औद्योगिक इकाइयों को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सरकार औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने में असमर्थ थी। मध्य प्रदेश में लोड शेडिंग छोटी इकाइयों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। लाभार्थियों ने बताया कि लोड शेडिंग ने उनके उत्पादन को प्रभावित किया और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत बढ़ गई।

तालिका 2: योजनाओं में नमूना लाभार्थियों की इकाइयों को चलाने में आने वाली समस्या

सामान		लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
यूनिट चलाने में आने वाली समस्या	हाँ	297	99
	नहीं	3	1
		300	100
इकाई चलाने में आने वाली समस्या की प्रकृति	बिजली की विफलता	162	54
	धन की कमी	267	89
	संचालन की उच्च लागत	78	26
	किराये/खरीद पर परिसर प्राप्त करना	60	20
	कच्चा माल प्राप्त करना	66	22

जिले में योजना लाभार्थियों के लिए कार्यशील पूंजी के लिए धन की कमी एक प्रमुख चिंता का विषय है। धन की कमी के कारण वे अपनी इकाइयों का प्रभावी ढंग से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए, उन्हें अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है और उनके लाभ मार्जिन में कमी आ सकती है। तालिका के अनुसार, 89 प्रतिशत उत्तरदाता इकाई चलाने में धन की कमी से प्रभावित हैं।

परिचालन की उच्च लागत लाभार्थियों के सामने एक और समस्या है। 26 प्रतिशत लाभार्थियों ने महसूस किया कि परिचालन की लागत अधिक होने के कारण वे स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। चुंगी शुल्क, स्पेयर पार्ट्स की लागत, ईंधन की लागत आदि लागत बढ़ाने वाली मुख्य वस्तुएँ हैं, जिससे सेवा और औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ प्रभावित हुईं। 20 प्रतिशत लाभार्थियों को किराए पर या खरीदकर परिसर प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ा, जबकि 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कच्चा माल प्राप्त करने में समस्या हुई।

निष्कर्ष

रोज़गार उन लोगों के लिए एक लाभदायक और लचीला करियर विकल्प हो सकता है जो इससे जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ और जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। यह स्वतंत्रता, संभावित वित्तीय लाभ और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, वित्तीय प्रबंधन और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होती है। अंततः, स्व-रोज़गार को अपनाने का निर्णय आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों, कौशल और जोखिम सहनशीलता पर आधारित होना चाहिए।

संदर्भ

1. साहा, अमित. उद्यमिता सशक्तिकरण: भारत में महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं पर एक अध्ययन।, 2018.
2. अहमद, जमील. स्वरोजगार को बढ़ावा देने में कौशल भारत की भूमिका: संभावनाएँ और चुनौतियाँ. विशेषांक, 2021, 185-190.
3. स्वरूपा, ग्लोरी और गोयल, रवि । स्वरोजगार के लिए कौशल विकास, 2019.
4. नाइक, अमी और पटेल, पूजा। उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए सरकारी योजनाएँ।, 2022. 10.1007/978-981-19-5747-5_2।
5. गुप्ता, पवन कुमार. भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलों का एक अध्ययन. मैनेजमेंट जर्नल फॉर एडवांस्ड रिसर्च. 2023, 3. 10.54741/mjar.3.6.5.
6. डॉ. अब्दाल और कुरैशी, सुमेरा और नरगिस, शमा और कौर, जसमीत और डबराल, डॉ. महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करने वाली भारतीय सरकार की योजनाओं का व्यापक विश्लेषण।, 2024. 10.18848/6z5mxs52.
7. सिंह, रागिनी. भारत में एमएसएमई के विकास में सरकारी सहायता योजनाओं की भूमिका पर एक अध्ययन. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. 2024;4:127-132. 10.3126/jem. v4i1.72897.
8. मुस्तफा, श्रीमती और खान, शुजाउद्दीन. गरीबी उन्मूलन में भारत सरकार की योजनाएँ. 2024;06:2913-2931. 10.6084/m9.figshare.2631195.
9. कौसर, अनिसुर और बोरमोन, सयानिका। बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के बीच भारत में स्वरोजगार: चल रहे अंतर्निहित निर्धारकों पर प्रकाश डालना। शोधकोश: जर्नल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। 2023, 4. 10.29121/shodhkosh. v4.i2.2023.2105।
10. एलिगनूर, बसवराज. भारत में स्टार्टअप पहल के लिए सरकारी योजनाओं पर एक वर्णनात्मक अध्ययन. 2023;47:113-120.
11. धाकर, शुभी और सिरोया, सुश्री. भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका पर एक अध्ययन। 2024;18:76-82.
12. कद्रोलकर, विलास. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार सृजन: कौशल सृजन कार्यक्रम का एक अध्ययन. प्रशिक्षण और विकास जर्नल. 2014;4:29-36. 10.5958/j.2231-069X.4.1.
13. सिंह, अमनकुमार. भारत सरकार की योजनाओं और पहलों पर एक अध्ययन: एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य, 2023. 10.13140/RG.2.2.19282.94407.
14. जेयादेवी जे, क्रिस्टीना और दुरैसामी, मूर्ति। ग्रामीण भारत में युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सरकारी योजनाएँ और समर्थन।, 2023.
15. सेल्वराज, रेणुका. भारत में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के विकास में सरकारी योजनाएँ. इंजीनियरिंग प्रबंधन और विज्ञान में प्रगतिशील अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल. खंड-1., 2020, 45-50.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.